

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3910
27.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थिति और विस्तार

3910. सुश्री स्वाति मालिवाल:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान संस्वीकृत, स्थापित और प्रचालनरत सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों की राज्य-वार और वर्ष-वार कुल संख्या कितनी-कितनी है;
- (ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ईवी चार्जिंग अवसंरचना के लिए राज्य-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि कितनी-कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के सापेक्ष चार्जिंग अवसंरचना की पर्याप्तता का आकलन किया है, यदि हां, तो ईवी-से-चार्जर अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) टियर-2 और टियर-3 शहरों में और राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित किए गए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है और स्थान के चयन के मानदंड क्या हैं; और
- (ङ) निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित आगामी तीन वर्षों में ईवी चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार के लिए रूपरेखा और लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना एक लाइसेंसरहित गतिविधि है और निजी उद्यमी भी इस गतिविधि में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा प्रदान की गई सूचनानुसार, 01.03.2026 तक इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवी पीसीएस) का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक** पर है।

(ख): 18 मार्च, 2026 तक फेम-II स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

स्कीम	स्वीकृत धनराशि	जारी धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
फेम-II	912.50	895.48	655.43

फेम-II स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए अनुदान का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं है।

इसके अतिरिक्त, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर ईवी पीसीएस की संस्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 24/03/2026 तक, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत ईवी पीसीएस के लिए कोई निधि जारी नहीं की गई है।

(ग): भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ): इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन संस्थापित करना एक लाइसेंसरहित गतिविधि है और निजी उद्यमी भी इस गतिविधि में भाग ले सकते हैं। टियर-2 और टियर-3 शहरों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवी पीसीएस) से संबंधित डेटा भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

वर्तमान में, निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित अगले तीन वर्षों में ईवी चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार के लिए कोई विशिष्ट रूपरेखा या लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। हालांकि, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर ईवी पीसीएस की संस्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

अनुलग्नक

01.03.2026 की स्थिति के अनुसार तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा संस्थापित और संचालित (संख्या में) किए गए ईवी पीसीएस का राज्य-वार विवरण।

राज्य	वित्तवर्ष 20-21	वित्तवर्ष 21-22	वित्तवर्ष 22-23	वित्तवर्ष 23-24	वित्तवर्ष 24-25	वित्तवर्ष 25-26 (01.03.26 तक)		पिछले पाँच वर्षों में संस्थापित कुल ईवी पीसीएस	कुल प्रचालनरत ईवी पीसीएस
						संस्थापित	प्रचालन में नहीं		
अंडमान और निकोबार	0	2	0	1	2	3		8	3
आंध्र प्रदेश	1	133	143	360	624	123		1384	1082
अरुणाचल प्रदेश	2	6	23	19	6	0	1	55	46
असम	7	39	119	186	173	2		526	461
बिहार	4	66	139	179	358	16		762	676
चंडीगढ़	6	4	4	1	4	5		24	23
छत्तीसगढ़	0	68	82	187	224	46		607	524
दिल्ली	35	37	58	100	344	79		653	542
गोवा	8	19	6	22	14	18		87	59
गुजरात	11	146	334	343	574	80		1488	1118
हरियाणा	26	115	205	344	674	23		1387	1167
हिमाचल प्रदेश	7	10	37	54	80	2		190	147
जम्मू एवं कश्मीर	0	22	65	53	95	0	15	220	140
झारखंड	4	44	73	91	196	19		427	324
कर्णाटक	36	153	542	478	1034	157		2400	2039
केरल	19	67	154	265	415	56		976	776
लद्दाख	0	2	0	0	14	8		24	23
लेह	0	0	0	0	5	0	5	0	0
लक्षद्वीप	0	1	0	0	0	0		1	1
मध्य प्रदेश	10	149	181	512	421	144		1417	1291
महाराष्ट्र	9	129	465	517	957	166		2243	1786
मणिपुर	1	15	17	19	19	0		71	64

राज्य	वित्तवर्ष 20-21	वित्तवर्ष 21-22	वित्तवर्ष 22-23	वित्तवर्ष 23-24	वित्तवर्ष 24-25	वित्तवर्ष 25-26 (01.03.26 तक)		पिछले पाँच वर्षों में संस्थापित कुल ईवी पीसीएस	कुल प्रचालनरत ईवी पीसीएस
						संस्थापित	प्रचालन में नहीं		
मेघालय	1	7	19	14	38	1		80	44
मिजोरम	0	0	2	11	16	1		30	15
नगालैंड	2	4	8	22	17	0		53	44
ओडिशा	0	90	121	268	257	30		766	618
पुडुचेरी	0	4	7	16	27	4		58	24
पंजाब	7	95	197	267	558	41		1165	908
राजस्थान	47	201	314	622	681	120		1985	1740
सिक्किम	0	0	2	10	1	0		13	12
तमिलनाडु	21	187	257	702	1064	55		2286	1677
तेलंगाना	24	98	155	380	730	137		1524	1173
त्रिपुरा	2	13	16	24	8	0		63	55
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के संघ राज्यक्षेत्र	0	1	5	4	5	3		18	8
उत्तर प्रदेश	19	252	649	1159	1034	171		3284	2893
उत्तराखंड	5	24	43	93	81	8		254	211
पश्चिम बंगाल	0	141	216	326	496	29		1208	1039
कुल	314	2344	4658	7649	11246	1547	21	27,737	22,753